एल. आर. एस. द्वारा विश्वनाथ घोष (मृत)। और अन्य

बनाम

गोबिंदा घोष एलियास गोबिंदा चंद्र घोष और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3672/2007)

14 मार्च, 2014

[जगदीश सिंह खेहर और एम. वाई. एक्बाल, जे. जे.]

विशिष्ट अनुपालना अधिनियम, 1963: धारा 16 (ग)-विशिष्ट अनुपालना-अनुबंध करने के लिए तैयारी और इच्छा-अभिनिर्धारित किया गयाः धारा 16 (ग) के अनुपालन के लिए अधिनियम के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि वादी धारा में उपयोग किए गए समान शब्दों में कहने के लिए अर्थात अनुबंध करने के लिए तैयार और अनुपालना की मांग करने वाले व्यक्ति की इच्छा का मतलब है कि अनुपालना का दावा करने वाले व्यक्ति ने अनुबंध रखा है- अपने दायित्व को पूरा करने और स्वीकार करने की तैयारी के साथ निर्वाह करना-जब अनुपालना का समय आता है-तत्काल मामले में, तथ्यों और घटनाओं के अनुक्रम से पता चलता है कि वादी-अपीलार्थी हमेशा तैयार और इच्छुक थे- अपने दायित्व का निर्वहन करें और समझौते के अपने हिस्से का पालन करें-इसलिए, उनकी ओर से अधिनियम की धारा 16(ग) आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन था।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 100-द्वितीय अपील-कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न-आयोजितः का अधिकार क्षेत्र दूसरी अपील पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय केवल इन तक ही सीमित है ऐसी अपील जिसमें विधि का सारवान प्रश्न शामिल हो।

वादी-अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी से 3000 रुपये का ऋण लिया और एक पंजीकृत कोबाला दिनांक 24.11.1964 को निष्पादित किया। उसी दिन, एक पंजीकृत इकरारनामा भी उनके बीच निष्पादित किया गया था। अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थियों को ऋण गणना के भुगतान पर पुनः हस्तांतरण की शर्तें हेतु 1990 में, अपीलकर्ताओं ने इसके खिलाफ वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया।

वादी-अपीलकर्ताओं ने रुपये 3000 का ऋण प्रतिवादियों से लिया-प्रतिवादियों ने दिनांक 24.11.1964 को एक पंजीकृत कोबाला निष्पादित किया। उसी दिन उनके बीच अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं को ऋण राशि के भुगतान पर पुनर्संवहन की शर्त हेतु एक निबंधित जी एकरारनामा का भी निष्पादन किया गया। 1990 में, अपीलकर्ताओं ने इसके खिलाफ वसूली के लिए मुकदमा बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट, 1940 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध दायर किया। मुंसिफ ने मुकदमा खारिज कर दिया। अपील पर, मामला मुंसिफ को वापस भेज दिया गया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ताओं को वादपत्र में संशोधन करने और विशिष्ट निष्पादन

की प्रार्थना जोड़ने का अवसर दिया जाए। अनुबंध के नियम और कानून के अनुसार नया निर्णय पारित करें।

अपीलकर्ता ने वादपत्र में संशोधन करते हुए मुकदमे की संपत्ति को पुनर्ग्रहण के लिए समझौते के संदर्भ में हस्तांतरित करने के लिए अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना की प्रार्थना जोड़ दी। मुंसिफ ने संशोधन आवेदन की अनुमति दी और अंततः यह कहते हुए मुकदमे पर फैसला सुनाया कि मुकदमा परिसीमन से बाधित नहीं है, यह मानते हुए कि संशोधन का आदेश मुकदमे की स्थापना की तारीख से संबंधित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील स्वीकार कर ली। इसलिए तत्काल अपील की।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया गया:

1. अपील के पहले दौर में प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित रिमांड के फैसले से पता चला कि दोनों पक्षों ने दो दस्तावेजों की व्याख्या, अर्थात् कोबाला और पुन: संवहन के समझौते पर अपनी प्रस्तुति दी। इससे यह भी पता चला कि प्रतिवादियों-प्रतिवादियों के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। उत्तर पत्र ने भूमि को पुनः प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उपयुक्त भूमि पर औशधानी की फसल के बाद। इसके बाद, वादी ने एक और पत्र जारी किया जिसमें फसल के बाद 3000/- रुपये के भुगतान पर मुकदमे

की भूमि को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी ने भी ऐसा जवाब दिया। पत्र फसल के बाद सूट भूमि को पुनः प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त करता है। इन निष्कर्षों से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि वादी को वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने के लिए मुंसिफ को एक निर्देश जारी किया गया था। अपीलीय अदालत ने प्रतिवादियों-प्रतिवादियों को अतिरिक्त लिखित आवेदन दाखिल करने का अवसर भी दिया। वाद में संशोधन किया गया और एक के लिए राहत दी गई तथा उक्त मुकदमे में विशिष्ट निष्पादन का डिक्री जोड़ा गया था। मुंसिफ ने मुकदमे को विशिष्ट निष्पादन के लिए यह कहते हुए डिक्री कर दिया कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है। [पैरा 7, 9 व 10] [1105-सी-ई; 1107-बी-ई]

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पता चला कि उच्च न्यायालय ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 और धारा 20 का उल्लेख करने के बाद माना कि चूंकि तत्परता और इच्छा को प्रमाणित और साबित नहीं किया गया है, मुंसिफ और प्रथम अपीलीय अदालत दोनों ने प्रतिबद्ध किया है विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे को डिक्री करने में त्रुटि। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि बंगाल साहूकार अधिनियम की धारा 36 के तहत एक मुकदमे को मूल रूप से विशिष्ट अनुपालना के लिए एक मुकदमे में परिवर्तित कर, मुकदमे की प्रकृति और चरित्र को बदल

दिया गया और वादी-अपीलकर्ताओं के पक्ष में इस तरह के संशोधन को गलत तरीके से अनुमति दी गई। [पैरा 14) [1108-बी-डी]

3. धारा 100 में कहा गया है कि अपीलीय डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील तभी की जाएगी जब उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इसमें आगे कहा गया है कि अपील का ज्ञापन अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को सटीक रूप से बताता है। यदि ऐसी कोई अपील दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय को अपील स्वीकार करते या उस पर विचार करते समय अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए और अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना चाहिए। इसके बाद अपील की सुनवाई इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों पर की जाएगी और प्रतिवादी को केवल कानून के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहस करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, इसके लिए परंतुक यह धारा अदालत को कारण दर्ज करने के बाद, तैयार नहीं किए गए कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुनवाई करने का अधिकार देती है।

यदि जी अपीलीय डिक्री से उत्पन्न अपील का ज्ञापन प्रदान किए गए तरीके से तैयार नहीं किया गया है

संहिता में, न्यायालय अपील के ज्ञापन को अस्वीकार कर सकता है या न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर संशोधन के प्रयोजनों के लिए

उसे वापस कर सकता है। हाईकोर्ट के आदेश से पता चला कि हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया था और दलीलें पूरी होने के बाद ही, कानून के कुछ प्रश्न तैयार किए गए थे और अपील पर आक्षेपित निर्णय पारित करके निर्णय लिया गया था। [पैरा 18, 20 और 22] [1109-जी-एच; 1110-ए-बी, एफ, एच; 1111-ए-बी]

शशिकुमार और अन्य बनाम कुन्नाथ चेलअप्पन नायर और अन्य (2005) 12 एससीसी 588: 2005 (4) पूरक एससीआर 363; गुरदेव कौर एवं अन्य बनाम काकी और अन्य (2007) 1 एससीसी 546: 2006 (1) पूरक एससीआर 27- पर आधारित किया।

4. तत्परता और इच्छा के सवाल पर, उच्च न्यायालय ने नीचे की दोनों अदालतों को पूरी तरह से उपेक्षित माना और तत्परता और इच्छा के बिंदु पर विचार करने में विफल रहा, जो निरंतर होना चाहिए और नीचे की दोनों अदालतें भी इस तत्परता पर विचार करने में विफल रहीं। और इच्छा को अभिवचित नहीं किया गया है और/या साबित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष के आधार पर विचारणीय न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द करके कानूनी त्रुटि की है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक मुकदमे में विशिष्ट प्रदर्शन में वादी को यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि वह उन दायित्वों को

पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक है जो वास्तव में प्रतिवादी के उपक्रम के लिए विचार का हिस्सा हैं। अधिनियम की धारा 16(सी) का अनुपालना में वादी के लिये आवश्यक नहीं है कि अनुभाग में उपयोग किए गए समान शब्दों में अभवचित करने के लिए कहा गया है यानी अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक। अनुपालना चाहने वाले व्यक्ति की तत्परता और इच्छा का मतलब है कि अनुपालना का दावा करने वाले व्यक्ति ने अपने दायित्व को पूरा करने और अनुपालना का समय आने पर अनुपालना को स्वीकार करने की तैयारी के साथ अनुबंध को बरकरार रखा है। [पैरा 24, 25, 26, 32] [1111-डी-एफ; 1112-सी-ई; 1117- ए-बी]

केदार लाल सील और अन्य. बनाम हरि लाल सील एआईआर (39) 1952 एससी 47: 1952 एससीआर 179; सैयद दस्तगीर बनाम टी.आर.एच गोपालकृष्ण शेट्टी (1999) 6 एससीसी 337: 1999 (1) सप्ली. एससीआर 351; एमएसटी. सुगनी बनाम रामेश्वर दास और ए एन आर एआईआर 2006 एससी ए 2172: 2006 (1) सप्ली. एससीआर 235- पर निर्भर।

अर्देशिर मामा बनाम फ्लोरा ससून 55 आईए (पीसी) 360; मकसूद अली एवं अन्य बनाम एस्कंदर अली 16 डीएलआर (19_64) 138 कॉर्ट एंड जी बनाम द एम्बरगेट, नॉटिंघम और बोस्टन और ईस्टर्न जंक्शन रेलवे कम्पनी (1851) 17 क्वीनस् बेंच रिपोर्टस् 127 पर निर्भर।

5. स्वीकृत है कि 1.12.1964 को प्रतिवादियों के पक्ष में विक्रय विलेख 3,000/- के भुगतान पर दो दस्तावेज़ निष्पादित किए गए थे। उसी दिन पुनर्संवहन का एक समझौता भी निष्पादित किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी निर्धारित समय के भीतर संपत्ति वापस लौटाने पर सहमत हुए। वादी ने वकील के माध्यम से एक नोटिस भेजकर प्रतिवादियों को सूचित किया कि शर्तों के अनुसार पुनर्संवहन के समझौते के लिए वादी ने 3,000/- रुपये की राशि की पेशकश की और उन्हें निष्पादित करने का अनुरोध किया। प्रतिवादियों ने किसी ने किसी बहाने से तारीख और समय टाल दिया। उसी नोटिस में, वादी ने प्रतिवादियों को उक्त राशि प्राप्त करने के बाद विक्रय पत्र निष्पादित करने की याद दिलाई। प्रतिवादी-उत्तरदाताओं ने दिनांक 29.4.1968 को वादी के नोटिस का जवाब भेजा जिसमें कहा गया था कि वे वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत करने के लिए तैयार थे, लेकिन भूमि पर धान उगाए जाने के कारण कुछ समय बाद ऐसा किया जा सकेगा। वादी ने फिर से दिनांक 6.6.1968 को एक नोटिस भेजा, जिसमें 29.4.1968 के उत्तर का हवाला दिया गया और प्रतिवादियों से धान की कटाई के बाद बिक्री विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया गया। आश्वासन के बावजूद, जब प्रतिवादी विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहे, तो वादी ने दिनांक 7.5.1970 को यह कहते हुए मुकदमा दायर किया कि वादी को भूमि पुनः प्राप्त करने और कब्जा लेने का पूरा अधिकार है। यद्यपि मुकदमा खारिज कर दिया गया, लेकिन

अपील में प्रथम अपीलीय अदालत ने अपील खारिज करते हुए आदेश में उल्लेख किया कि वादीगण ने मुंसिफ के निर्देशानुसार धनराशि विशिष्ट अनुपालना के निर्णय की तय तिथि से पूर्व जमा कर दी है। तथ्यों और घटनाओं के क्रम से पता चला कि वादी-अपीलकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करने और समझौते में अपना हिस्सा निभाने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थे। निर्विवाद तथ्य और घटनाएं विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (सी) की आवश्यकताओं के पर्याप्त अनुपालन के समान होंगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि करने वाले प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया जाता है। [पैरा 33, 34, 36] [1117-सी-जी; 1118-जी.एचर; 1120-ए.ई., एफ-जी]

मामला कानून संदर्भः

2005 (4) सप्ली. एससीआर 363 इस पर भरोसा किया	पैरा 16
2006 (1) सप्ली. एससीआर 27 इस पर भरोसा किया	पैरा 16
1952 एस. सी. आर. 179 इस पर भरोसा किया	पैरा 26
1999 (1) सप्ली. एससीआर 351 इस पर भरोसा किया	पैरा 27
2006 (1) सप्ली. एससीआर 235 इस पर भरोसा किया	पैरा 28
55 आई. ए. (पीसी) 360 उल्लेख किया गया	पैरा 29

16 डीएलआर (1964) 138 उल्लेख किया गया पैरा 30

(1851) 17 रानी की बेंच रिपोर्ट 127 उल्लेख किया गया पैरा 31

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3672/2007

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एस.ए.सं.244/1987 में निर्णय और आदेश दिनांकित 28.03.2005

एस.बी. सान्याल, आर. के. गुप्ता, एस. के. गुप्ता, एम. के. सिंह, बी. पी. गुप्ता, शेखर कुमार अपीलार्थियों की ओर से।

बिजन कुमार घोष प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एम. वाई. एक्बाल, जे. द्वारा दिया गया था

1. यह अपील 1987 के एसए नंबर 244 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित 28.3.2005 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री को उलट दिया गया है और मुकदमा खारिज कर दिया गया है। यह मानते हुए कि मुकदमा स्वयं परिसीमन और प्रासंगिक दलीलों और सबूतों की कमी के कारण बाधित था, वादी-अपीलकर्ता को विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री प्राप्त करने और मुकदमे की संपत्ति के पुन: हस्तांतरण के लिए वंचित कर दिया गया।

2. मामले के तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं।

3. वादी-अपीलकर्ताओं को पैसे की जरूरत थी, उन्होंने प्रतिवादी से 3,000/- रुपये का ऋण लिया और एक पंजीकृत कोबाला दिनांक 24.11.1964 को निष्पादित किया। उसी दिन, अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं को ऋण राशि के भुगतान पर पुनर्संवहन की शर्तों को निर्धारित करने वाले पक्षों के बीच एक पंजीकृत इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था।

4. वर्ष 1970 में, अपीलकर्ताओं ने बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट, 1940 की धारा 36 के तहत उप-विभागीय मुंसिफ, बंगाण के समक्ष प्रतिवादियों के खिलाफ 1970 का टाइटल सूट नंबर 215 का मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे का विरोध किया गया। प्रतिवादी-प्रतिवादी, जिसमें कहा गया है कि वादी द्वारा निष्पादित पूर्वोक्त विक्रय विलेख मुकदमे की संपत्ति की बिक्री से बाहर था और कब्जा भी उत्तरदाताओं को दे दिया गया था। विद्वान मुंसिफ ने निर्णय दिनांक 20.12.1973 के अनुसार मुकदमा खारिज कर दिया। वादी ने तब उक्त फैसले के खिलाफ 1974 की शीर्षक अपील संख्या 350 के तहत अपील दायर की। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट को अनुमति देने के निर्देश के साथ मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। वादी-अपीलकर्ताओं को वाद-विवाद में संशोधन करने और अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए प्रार्थना जोड़ने और कानून के अनुसार नया निर्णय पारित करने का अवसर दिया गया।

5. रिमांड के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने 1.3.1975 को आवेदन दायर करके वादपत्र में संशोधन किया, जिसमें पुनः हस्तांतरण के लिए समझौते के संदर्भ में मुकदमे की संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना के लिए प्रार्थना शामिल की गई। संशोधन के लिए उक्त आवेदन की अनुमति दी गई थी और विद्वान मुंसिफ ने अतिरिक्त विवाद्यक विरचित किया था, और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अंततः यह कहते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि मुकदमा परिसीमा से बाधित नहीं था। मुंसिफ की अदालत ने माना कि संशोधन का आदेश मुकदमे की स्थापना की तारीख से संबंधित है और इसलिए, मुकदमे को परिसीमा द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादियों-प्रतिवादियों ने 1983 की शीर्षक अपील संख्या 836 के तहत अपील दायर की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर खारिज कर दिया। इसके बाद उत्तरदाताओं ने दूसरी अपील दायर की, जिसे अंततः प्रतिवादी-प्रतिवादियों के पक्ष में स्वीकार कर लिया गया और मुंसिफ और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दोनों अदालतों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया। अतः वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए और अपील की अनुमति देते समय उन पर विचार किया:

"1) क्या नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों ने इस तथ्य के बावजूद अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना के लिए डिक्री देने में कानून में गलती की है कि विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक दावे वादपत्र में अनुपस्थित थे ।

2) क्या अभिलेखों में मौजूद सामग्री के आधार पर नीचे दिए गए दोनों विद्वान न्यायालयों को यह मानना चाहिए था कि वादी यह दलील देने और यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वे अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थे।

3) क्या मौजूदा मामले में अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए प्रार्थना परिसीमा द्वारा वर्जित है।

4) क्या जिस संशोधन के लिए प्रार्थना की गई थी, उसे सही तरीके से अनुमति दी गई थी और क्या उक्त संशोधन के आधार पर नीचे की दोनों अदालतों ने मुकदमे का फैसला सही ढंग से किया था।"

7. इससे पहले कि हम मामले को आगे बढ़ाएं, पहले अपील के पहले दौर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित रिमांड के फैसले को देखना उचित होगा, जिसका शीर्षक

1974 की अपील संख्या 350 है, जिसे मुंसिफ द्वारा पारित फैसले के खिलाफ प्राथमिकता दी गई थी। वादी-अपीलकर्ताओं का मुकदमा खारिज करना। फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों पक्षों ने दो दस्तावेजों, अर्थात् कोबाला और पुनः संवहन के समझौते की व्याख्या पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। इससे यह भी पता चलता है कि पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था (प्रदर्श 'बी' और 'बी 1') जिसके बाद प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने उत्तर पत्र में भूमि को फिर से हासिल करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सूट वाली भूमि पर ऐशपैडी की फसल के बाद। इसके बाद, वादी ने दिनांक 6.6.1968 को एक और पत्र जारी किया जिसमें 3000/- रुपये के भुगतान पर फसल के बाद वाद की भूमि को हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की गई (प्रदर्श 'बी2')। प्रतिवादी ने भी ऐसे पत्र (प्रदर्श 'बी3') का जवाब देते हुए फसल के बाद वाद भूमि को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।

8. पत्रों के आदान-प्रदान और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपीलीय न्यायालय ने माना कि वादी-अपीलकर्ताओं को समझौते के संदर्भ में अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना का अवसर दिया जाना चाहिए। अपील में

पारित निष्कर्ष और आदेश का प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है:

"वादी-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी को एक समझौते (एक्सटेंशन 1) के संदर्भ में अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना का अवसर दिया जाना चाहिए। कानून के तहत समय का सार नहीं है भूमि की बिक्री के मामले में अनुबंध। पक्षकारों ने पारस्परिक रूप से समय बढ़ाया, जैसा कि उनके बीच पारित पत्रों से संकेत मिलता है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इस तथ्य के लिए नहीं बोलते हैं कि वादी बंगाल मनी ऋणदाता अधिनियम के प्रावधान के तहत लेनदेन को ऋण के रूप में मानने के इच्छुक हैं। दूसरी ओर, वे पुनर्खरीद विस्तार के समझौते पर वापस आने के इच्छुक हैं। लेकिन मुकदमा बंगाल मनी लेंडर्स अधिनियम की धारा 36 के तहत एक के रूप में तैयार किया गया है और इस तरह से कोई राहत नहीं दी जा सकती है विशिष्ट अनुपालना के माध्यम से। अब तक न्याय के उद्देश्य के लिए में वादी को उचित रूप से वादपत्र में संशोधन करके और अपेक्षित अदालती शुल्क के भुगतान और औपचारिकताओं के अनुपालन पर अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना के लिए प्रार्थना

शामिल करने का विशिष्ट अनुपालना के लिए एक वाद का अवसर दिया जाना चाहिए।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने वादी को ऐसा अवसर देने पर आपत्ति जताई है क्योंकि प्रस्तावित संशोधन से मुकदमे की प्रकृति बदल जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। वादी की मुख्य प्रार्थना समझौते के संदर्भ में या तो लेनदेन को फिर से खोलकर या अनुबंध के विशिष्ट अनुपालना द्वारा भूमि की बहाली के लिए है।

इन सब पर विचार करते हुए, न्याय की दृष्टि से, मैं वादी पक्ष को मेरे फैसले में ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में वाद में संशोधन करने का अवसर देने के लिए मुकदमे को वापस भेजता हूं। परिणामतः अपील सफल होती है। अपील के ज्ञापन पर सही मुहर लगी हुई है। इसलिए, आदेश दिया गया कि अपील को बिना किसी लागत के प्रतियोगिता में स्वीकार किया जाए। विद्वान मुंसिफ के फैसले और डिक्री को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है। वादी को अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए प्रार्थना करने के लिए वाद में संशोधन करने का अवसर देने के लिए मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाए। वादी को ऐसा संशोधन करने के

लिए प्रतिवादी को 30/- रुपये (तीस रुपये) की लागत का भुगतान करना होगा। प्रतिवादियों को अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने का अवसर मिलेगा। इस मुकदमे का रिकॉर्ड प्राप्त होने के दो महीने के भीतर संशोधन प्रभावी होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। संशोधन के बाद विद्वान मुंसिफ यदि पक्षकार चाहें तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर और वादी की अतिरिक्त प्रार्थना के संदर्भ में रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर मुकदमे का निर्णय करेगा।"

9. रिमांड के उपरोक्त निर्णय में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि वादी को 30/- रुपये की लागत के भुगतान पर वाद में संशोधन करने की अनुमति देने के लिए विद्वान मुंसिफ को एक निर्देश जारी किया गया था। अपीलीय अदालत ने प्रतिवादियों-प्रतिवादियों को अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने का अवसर भी दिया।

10. उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में, वादपत्र में संशोधन किया गया और उक्त मुकदमे में विशिष्ट निष्पादन की डिक्री के लिए राहत जोड़ी गई। विद्वान मुंसिफ ने अतिरिक्त वाद तैयार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद मुकदमे को विशिष्ट निष्पादन के लिए यह

कहते हुए डिक्री कर दिया कि मुकदमा परिसीमा से बाधित नहीं है। डिक्री पारित करते हुए वादी-अपीलकर्ता को प्रतिफल राशि रू0 3,000/- जमा करने का निर्देश दिया गया।

11. विद्वान मुंसिफ ने माना कि संशोधन की अनुमति देने और विशिष्ट निष्पादन की डिक्री के लिए राहत जोड़े जाने के बाद, यह माना जाना चाहिए कि विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा वाद की स्थापना की तारीख यानी 7.5.1970 को दायर किया गया था।

12. उक्त निर्णय और मुंसिफ द्वारा पारित डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने 1983 की शीर्षक अपील संख्या 836 के रूप में एक अपील को प्राथमिकता दी। उक्त अपील पर सुनवाई की गई और अंततः प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमा अच्छी तरह से दायर किया गया था। परिसीमा की अवधि और इसे परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं किया गया था, क्योंकि वादपत्र का संशोधन वादपत्र की प्रस्तुति की तारीख से संबंधित था।

13. इसके बाद बचाव पक्ष-प्रतिवादियों ने फैसले के विरूद्ध 1987 की एसए नंबर 244 की दूसरी अपील दायर की। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्ष को उलट दिया और अनुमति देकर इसे अलग रखा।

14. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय, विशिष्ट अनुपालना अधिनियम की धारा 16 और धारा 20 का उल्लेख करने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्धारित करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि तैयारी और इच्छा को अभिवचित और साबित नहीं किया गया है, ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने विशिष्ट अनुपालना के लिए मुकदमे को डिक्री करने में त्रुटि की है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि बंगाल साहूकार अधिनियम की धारा 36 के तहत एक मुकदमे को विशिष्ट अनुपालना के लिए एक मुकदमे में परिवर्तित करके, मूल रूप से मुकदमे की प्रकृति और चरित्र को बदल दिया गया था और वादी-अपीलकर्ताओं के पक्ष में ऐसे संशोधनों को गलत तरीके से अनुमति दी गई है। .

15. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस.बी. सान्याल ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "कोड") की धारा 100 की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं करने के कारण उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय कानून की दृष्टि से दूषित है। दरअसल, हाईकोर्ट ने दूसरी अपील से निपटने में गलत प्रक्रिया अपनाई है।

16. श्री सान्याल ने आगे तर्क दिया कि अपील पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को उक्त अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना होगा और उत्तरदाताओं को नोटिस देने के बाद ही कानून

के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सुनवाई का अवसर देना होगा। अंततः अपील पर निर्णय करेगा। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने शशिकुमार और अन्य बनाम कुन्नथ चेल्लप्पन नायर और अन्य , (2005) 12 एससीसी 588 और गुरदेव कौर और अन्य बनाम काकी और अन्य , (2007) 1 एससीसी 546 के मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। हमें श्री सान्याल की प्रस्तुतिकरण में बल पाते है।

17. संहिता की धारा 100 दूसरी अपील के संबंध में प्रावधान बताती है जो इस प्रकार है: -

> "100. दूसरी अपील:- (1) इस संहिता के मुख्य भाग में या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
>
> (2) इस धारा के तहत एकपक्षीय रूप से पारित अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।

(3) इस धारा के तहत अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।

(5) अपील की सुनवाई इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है:

बशर्ते कि इस उपधारा में किसी भी बात को दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उसके द्वारा तैयार नहीं किए गए कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील सुनने की अदालत की शक्ति को छीनने या कम करने वाला नहीं माना जाएगा, यदि वह संतुष्ट है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।"

18. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि अपीलीय डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील तभी की जाएगी जब उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इसमें आगे कहा गया है कि अपील का ज्ञापन अपील में

शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताता है। यदि ऐसी कोई अपील दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय को अपील स्वीकार करते या उस पर विचार करते समय अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए और अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना चाहिए। इसके बाद अपील की सुनवाई इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्नों पर की जाएगी और प्रतिवादी को केवल कानून के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहस करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, इस धारा का प्रावधान अदालत को कारण दर्ज करने के बाद तैयार नहीं किए गए कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुनवाई करने का अधिकार देता है।

19. आदेश XLI, संहिता का नियम (3) भी यहां नीचे उद्धृत करने योग्य है:-

> "3. ज्ञापन की अस्वीकृति या संशोधन:-
>
> (1) जहां अपील का ज्ञापन यहां निर्धारित तरीके से तैयार नहीं किया गया है, इसे खारिज कर दिया जा सकता है, या एक समय के भीतर संशोधित होने के उद्देश्य से अपीलकर्ता को वापस कर दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा या उसी समय संशोधित किया जाएगा।
>
> (2) जहां न्यायालय किसी ज्ञापन को अस्वीकार करता है, वह ऐसी अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करेगा।

(3) जहां अपील के ज्ञापन में संशोधन किया जाता है, न्यायाधीश, या ऐसा अधिकारी जिसे वह इस संबंध में नियुक्त करता है, संशोधन पर हस्ताक्षर करेगा या हस्ताक्षर करेगा।

20. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी अपीलीय डिक्री से उत्पन्न अपील का ज्ञापन संहिता में दिए गए तरीके से तैयार नहीं किया गया है, तो न्यायालय अपील के ज्ञापन को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर अस्वीकार कर सकता है या संशोधन के प्रयोजनों के लिए उसे वापस कर सकता है।

21. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने जो किया है वह उसके दिनांक 13.1.1987 के आदेश से स्पष्ट है। आदेश इस प्रकार है:- "इस अपील पर सभी आधारों पर सुनवाई की जाएगी और एक नियम जारी किया जाएगा और प्रार्थना के अनुसार रोक लगाई जाएगी"

22. उपरोक्त आदेश से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार करते समय कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया है और बहस समाप्त होने के बाद ही कानून के कुछ प्रश्न तैयार किए गए थे और अपील पर आक्षेपित निर्णय पारित करके निस्तारण किया गया था।

23. इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि दूसरी अपील पर विचार करने का उच्च न्यायालय का

अधिकार क्षेत्र केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिसमें कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। संहिता की धारा 100 उच्च न्यायालय को अपील स्वीकार करते समय पहले कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने का आदेश देती है। दूसरे शब्दों में, अपील की सुनवाई से पहले कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। चूँकि ऐसा नहीं किया गया है, आक्षेपित निर्णय कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण है।

24. तत्परता और इच्छा के सवाल पर, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा करने के बाद अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया एकमात्र निष्कर्ष यहां नीचे दिया गया है: -

> "मेरे विचार में, नीचे की दोनों अदालतें तत्परता और इच्छा के बिंदु पर पूरी तरह से उपेक्षित और विचार करने में विफल रहीं, जो निरंतर होनी चाहिए और नीचे की दोनों अदालतें इस बात पर भी विचार करने में विफल रहीं कि इस तत्परता और इच्छा को अभिवचित नहीं किया गया है और/या साबित नहीं किया गया है। नीचे दिए गए विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को स्कैन किए बिना, विद्वान

विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को गलत तरीके से बदल दिया और अपने वैधानिक दायित्वों और/या कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा।

ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए और ऊपर संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान ट्रायल न्यायाधीश के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दोनों को रद्द कर दिया जाता है।

इसलिए मुकदमा खारिज किया जाता है।

तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

तथ्यों और परिस्थितियों में पक्षकारों को अपना-अपना खर्चा वहन करना होता है।

निचली अदालत के रिकॉर्ड को तुरंत नीचे की अदालतों में भेजा जाए।

यदि आवेदन किया जाता है तो तत्काल ज़ेरॉक्स प्रमाणित प्रति पार्टियों को यथासंभव शीघ्रता से दी जाएगी।"

25. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द करने में कानून की त्रुटि की है।

26. कानून का यह सुस्थापित प्रस्ताव है कि विशिष्ट अनुपालना के मुकदमे में वादी को यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि वह उन दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक है जो वास्तव में प्रतिवादी के उपक्रम के विचार का हिस्सा हैं। अधिनियम की धारा 16 (सी) के अनुपालन के लिए वादी के लिए धारा में प्रयुक्त समान शब्दों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है अर्थात अनुबंध का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक है। यदि अदालत को अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने की तत्परता और इच्छा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त तथ्य और सबूत रिकॉर्ड पर लाए जाते हैं, तो वादपत्र में विशिष्ट शब्दों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप मुकदमा खारिज नहीं किया जाएगा। केदार लाल सील और अन्य के मामले में . बनाम हरि लाल सील , एआईआर (39) 1952 एससी 47 के मामले में इस न्यायालय ने माना है कि न्यायालय केवल दलील की तकनीकीता के आधार पर दावे को खारिज करने में देरी करेगा। न्यायालय ने टिप्पणी की :

> "51. जब बात का सार मौजूद हो और दूसरे पक्ष पर कोई पूर्वाग्रह न हो, तो मैं केवल दलील की तकनीकीता के आधार पर दावा खारिज करने में धीमा होऊंगा, भले ही वाद कितना भी अव्यवहारिक या अकलात्मक ढंग से लिखा गया हो। किसी भी घटना में, अदालत हमेशा वादी को ऐसी सामान्य या अन्य राहत देने के लिए खुली होती है, जिसे वह ठीक

उसी सीमा तक समझती है, जैसे कि यह मांगी गई थी, बशर्ते कि किसी भी अवसर पर दूसरे पक्ष के प्रति लागत से अधिक मुआवजा न दिया जाए। "

27. सैयद दस्तगीर बनाम टीआर गोपालकृष्ण शेट्टी, (1999) 6 एससीसी 337 के मामले में, इसी तरह के विवाद्यक के संदर्भ में न्यायालय ने कहा:

"9. इसलिए उठाए गए मुद्दे का पूरा पहलू यह है कि विशेष रूप से धारा 16 (सी) के संदर्भ में एक याचिका का अर्थ कैसे लगाया जाए और वादी को अपनी याचिका के संदर्भ में क्या दायित्वों का पालन करना है और क्या उसकी याचिका का पालन करना है वादी को पूर्वोक्त अनुभाग की आवश्यकता के अनुरूप नहीं माना जा सकता है, या क्या इस अनुभाग में विशिष्ट शब्दों की आवश्यकता है कि उसने अनुबंध का पालन किया है या हमेशा तैयार है और अनुबंध के अपने हिस्से को निष्पादित करने के लिए तैयार है। किसी भी दलील में, अदालतों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दलील कला और विज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि राहत के लिए किसी के मामले के तथ्य और कानून को शब्दों के माध्यम से रखने की अभिव्यक्ति है। ऐसी अभिव्यक्ति स्पष्ट,

सटीक, कभी-कभी अस्पष्ट हो सकती है लेकिन फिर भी यह पूरी दलील पढ़कर ही यह पता लगाया जा सकता है कि वह क्या कहना चाहता है, यह याचिका तैयार करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। भारत में अधिकांश दलीलें वकील द्वारा तैयार की जाती हैं, इसलिए दलीलों में उपरोक्त अंतर है जो अनिवार्य रूप से एक से दूसरे में भिन्न होता है। इस प्रकार, किसी दलील के पीछे की सच्ची भावना को जानने के लिए इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह किसी को क़ानून के तहत आवश्यक अपने दायित्वों को पूरा करने से विचलित नहीं करता है। लेकिन यह जांचने के लिए कि क्या उसने अपने दायित्वों का पालन किया है, किसी को याचिका का सार और सार देखना होगा। जहां किसी क़ानून के लिए किसी तथ्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है तो उसे किसी भी रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। एक ही दलील को अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग शब्दों के माध्यम से कहा जा सकता है; फिर इसे केवल किसी विशेष नामकरण या शब्द तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है। जब तक किसी क़ानून के लिए विशेष रूप से किसी विशेष रूप में याचिका की आवश्यकता नहीं होती, यह किसी भी रूप में हो सकती है। ऐसी दलील देने के लिए किसी

विशिष्ट वाक्यांशविज्ञान या भाषा की आवश्यकता नहीं है। धारा 16(सी) में भाषा के लिए किसी विशिष्ट वाक्यांशविज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह है कि वादी को यह कहना चाहिए कि उसने अनुबंध के अपने हिस्से का पालन किया है या हमेशा से रहा है और करने को तैयार है। इसलिए "तत्परता और इच्छा" का अनुपालन भावना और सार में होना चाहिए न कि अक्षरशः और रूप में। इसलिए किसी क़ानून के सटीक शब्दों के यांत्रिक उत्पादन पर ज़ोर देना सार के बजाय स्वरूप पर ज़ोर देना है। इसलिए यदि पहले से ही अनुरोध किया गया हो तो रूप की अनुपस्थिति किसी सार को भंग नहीं कर सकती है।"

28. सुगनी बनाम रामेश्वर दास और अन्य , एआईआर 2006 एससी 2172, इस न्यायालय ने कहा कि "17. अंतिम तथ्य न्यायालय द्वारा जिन आधारों पर निष्कर्ष निकाले गए थे, उनकी जांच करना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह सच है कि निचली अपीलीय अदालत को आमतौर पर विश्वसनीयता के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए गवाहों को खारिज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां तक कि जहां उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए गवाहों को खारिज कर दिया है, वहीं दूसरी अपील में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है, जब ऐसा हो पाया गया कि अपीलीय अदालत ने ऐसा करने के लिए संतोषजनक कारण दिए हैं।

ऐसे मामले में जहां परिस्थितियों के एक सेट से दो निष्कर्ष संभव हैं। निचली अपीलीय अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाना है अनुमति योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय अदालत की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकता जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष गलत थे और लागू कानून के अनिवार्य प्रावधानों या उसके आधार पर तय स्थिति के विपरीत थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई घोषणाएँ, या अस्वीकार्य साक्ष्यों पर आधारित थीं या बिना साक्ष्य के की गई थीं।

18. यदि कानून का प्रश्न जिसे सारगर्भित प्रश्न कहा गया है, संबंधित उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ या प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है, तो यह मामले के तथ्यों पर केवल गलत अनुप्रयोग है। इसे कानून का सारगर्भित प्रश्न नहीं कहा जाएगा। जहां कानूनी मुद्दे की पैरवी नहीं की गई है या किसी तथ्यात्मक प्रारूप के अभाव में पक्षों के बीच उठता हुआ पाया गया है, तो किसी वादी को दूसरी अपील में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल तथ्यों, दस्तावेजी सबूतों या प्रविष्टियों के अर्थ और दस्तावेज़ की सामग्री की सराहना को कानून का एक बड़ा सवाल उठाने वाला नहीं माना जा सकता है। लेकिन जहां यह पाया जाता है कि पहली अपीलीय अदालत ने उस

क्षेत्राधिकार को मान लिया है जो उसमें निहित नहीं था, तो इसे कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए दूसरी अपील में फैसला सुनाया जा सकता है। जहां पहली अपीलीय अदालत को न्यायिक तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, इसे दूसरी अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले कानून या प्रक्रिया की त्रुटि नहीं कहा जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम रामकृष्ण गोविंद मोरे , एआईआर 1976 एससी 830 में इस न्यायालय ने कहा कि क्या ट्रायल कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का अलग ढंग से प्रयोग नहीं करना चाहिए था, यह हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाले कानून का सवाल नहीं है।"

29. अर्देशिर मामा बनाम फ्लोरा सैसून , 55 आईए (पीसी) 360 के मामले में , न्यायिक समिति के उनके आधिपत्य ने देखा कि

> "जहां घायल पक्ष ने कानून के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया, जैसा कि वर्तमान मामले में है, अनुबंध की जड़ में, उसने इस तरह अनुबंध को समाप्त मान लिया और खुद को अपने दायित्वों से मुक्त मान लिया। उसके द्वारा किसी भी आगे के अनुपालना पर न तो विचार किया गया और न ही उसे प्रस्तुत करना पड़ा। दूसरी ओर, विशिष्ट अनुपालना के लिए एक मुकदमे में, उसने व्यवहार किया और न्यायालय द्वारा अनुबंध को अभी भी विद्यमान मानने की अपेक्षा की

गई। उसके पास उस मुकदमे में आरोप लगाने के लिए था, और यदि तथ्य का पता लगाया गया था, तो उसे अनुबंध की तारीख से लेकर अनुबंध की तिथि तक निरंतर तत्परता और इच्छा साबित करने की आवश्यकता थी। सुनवाई का समय, उसकी ओर से अनुबंध का पालन करने के लिए। उस कथन को पूरा करने में विफलता के कारण उसका मुकदमा अपरिहार्य रूप से खारिज हो गया।"

30. उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए, मकसूद अली और अन्य के मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट।

बनाम एस्कंदर अली, 16 डीएलआर (1964) 138, निम्नानुसार देखा गया:

"25. जहां तक इस तरह की तत्परता और इच्छा की पैरवी में कोई स्पष्ट दावा करने का सवाल है, हमारा विचार है कि यद्यपि इसमें संदेह हो सकता है कि यह दलील देने की अपरिवर्तनीय प्रथा है, और यदि हम ऐसा कह सकते हैं , एक वांछनीय प्रथा, जिसे मामले के प्रतिद्वंद्वी को स्पष्ट और स्पष्ट नोटिस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कानून का एक नियम है जो मुकदमे की संरचना को ही दोषपूर्ण बना देगा या इसके बिना वाद-पत्र पर कार्रवाई का उचित कारण सामने नहीं

आएगा। इसलिए, हम विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस तरह के कथन के अभाव में वर्तमान मुकदमा विफल होने के लिए बाध्य है।"

31. कॉर्ट और जी बनाम द एम्बरगेट, नॉटिंघम और बोस्टन और ईस्टर्न जंक्शन रेलवे कंपनी, (1851) 17 क्वींस बेंच रिपोर्ट 127 के मामले में, न्यायालय ने कहा कि

"सामान्य अर्थ में तत्परता और इच्छा के इस तरह के अभिवचन का अर्थ है यह अवश्य होना चाहिए कि अनुबंध का पूरा न होना वादी की गलती नहीं थी, और यदि प्रतिवादियों ने इसका त्याग नहीं किया होता तो वे इसका निपटारा कर चुके होते और इसे पूरा करने में सक्षम होते। माल का निर्माण किया जाना है? यदि, एक हिस्सा स्वीकार करने के बाद, वे शेष के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं, और उन्हें स्वीकार नहीं करने का संकल्प लिया है, तो सामग्री और श्रम की बेकार बर्बादी से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता है, जो संभवतः बढ़ सकता है उनके विरुद्ध मुआवजे की राशि दी जाएगी।"

32. कुल मिलाकर, हमारी सुविचारित राय में, अनुपालना चाहने वाले व्यक्ति की तत्परता और इच्छा का मतलब है कि प्रदर्शन का दावा करने

वाले व्यक्ति ने अपने दायित्व को पूरा करने और अनुपालना का समय आने पर अनुपालना को स्वीकार करने की तैयारी के साथ अनुबंध को कायम रखा है।

33. यहां पहले चर्चा किए गए सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, अब हम वादी-अपीलकर्ताओं के आचरण और उनके दायित्वों के प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए कार्य पर विचार करेंगे। इन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

i) यह स्वीकृत स्थिति है कि 1.12.1964 को, दो दस्तावेज़ निष्पादित किए गए थे। 3,000/- रुपये के भुगतान पर प्रतिवादियों के पक्ष में विक्रय विलेख।

ii) उसी दिन पुनर्संवहन का एक समझौता भी निष्पादित किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी निर्धारित समय के भीतर संपत्ति वापस लौटाने के लिए सहमत हुए;

iii) पुन: विलेख में निर्धारित समय की समाप्ति से पहले कन्वेयंस, वादी ने एक वकील के माध्यम से एक नोटिस भेजकर प्रतिवादियों को सूचित किया कि पुन: कन्वेयंस समझौते की शर्तों के अनुसार वादी ने 3,000/- रुपये की राशि जमा की है और उनसे विक्रय पत्र निष्पादित करने का अनुरोध किया है। प्रतिवादियों ने किसी न किसी बहाने से तारीख

और समय को टाल दिया। उसी नोटिस में, वादी ने प्रतिवादियों को उपरोक्त राशि प्राप्त करने के बाद विक्रय पत्र निष्पादित करने की याद दिलाई।

iv) प्रतिवादियों-प्रतिवादियों ने 29.4.1968 को वादी के नोटिस का जवाब भेजा जिसमें कहा गया था कि वे वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने और पंजीकृत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भूमि पर धान उगाए जाने के कारण कुछ समय पश्चात ऐसा किया जा सकता है। दिनांक 29.4.1968 का उत्तर यहां नीचे दिया गया है:

"नोटिस

1. श्री बिस्वनाथ घोष

2. श्री गुरु पद घोष

3. तारक दासी घोष, ग्राम नारीकेला, डाकघर गायघाटा, मेरे मुवक्किल श्री नरेंद्र नाथ घोष और श्री हरेंद्र नाथ घोष के निर्देशों और सलाह के तहत और उक्त नोटिस दिनांक 22.4.68 के उत्तर में। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि रुपये की पेशकश के संबंध में उत्तर के तहत उक्त नोटिस के कथन और सामग्री। आपके द्वारा 3000/- का भुगतान करना तथा उनसे अनुरोध करना कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में पौस की फसल की कटाई के बाद पूस की फसल की

कटाई तथा उक्त विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत करना पूर्णतया गलत है।

उक्त नोटिस के तहत विचाराधीन भूमि को मेरे मुवक्किल ने आपकी जानकारी में और बिना किसी आपत्ति के बैसाक के चौथे दिन औश धान दिखाया है और उक्त धान के बीज कुछ हद तक उग आए हैं, मेरे मुवक्किल बिक्री को निष्पादित करने और पंजीकृत करने के लिए तैयार हैं। 3000/- रुपये की उक्त राशि की स्वीकृत रसीद के बाद हमारी अपनी लागत पर आपके पक्ष में विलेख। दिनांक 29.4.68 को उक्त धान की कटाई के बाद भाद्र माह के भीतर

एसडी/- रवीन्द्र नाथ दत्ता एडवोकेट 29.4.68"

v) वादी ने 6.6.1968 को फिर से एक नोटिस भेजा जिसमें 29.4.1968 के उत्तर का हवाला दिया गया और प्रतिवादियों से धान की कटाई के बाद विक्रय पत्र निष्पादित करने का अनुरोध किया गया। उक्त पत्र भी यहां नीचे दिया गया है:

"प्रेषक:

नीरेंद्रनाथ बसु, वकील, बोनगांव, पीओ डीटी। 24 परगना से, प्रेषिति 1.श्री नरेंद्र नाथ घोष) स्वर्गीय हजारी लाई घोष के पुत्र

2. श्री हरेन्द्र नाथ घोष) ग्राम नारीकेला, डाकघर गायघाटा, जिला के निवासी। 24 परगना, दिनांक 6 जून 1968 को बोनगाँव में।

महोदय, मेरे मुवक्किल श्री बिस्वनाथ घोष, श्री गुरुपद घोष, श्री तारक बासी घोष के निर्देश के तहत आपके वकील रवीन्द्र नाथ दत्ता की ओर से भेजे गए पत्र दिनांक 29/4/1968 के अनुसरण में। आपको सूचित किया जाता है कि भाद्र माह के भीतर 'औष धान' की कटाई के बाद और उक्त माह के भीतर रु. की प्रासि स्वीकार की जाती है। मेरे मुवक्किल से 3000/- नकद और मेरे मुवक्किल के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित और पंजीकृत करें और मेरे मुवक्किलों के पक्ष में खाली कब्जा प्रदान करें अन्यथा आप दिनांक 6.6.68 को सभी लागतों और क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

एसडी/- नरेंद्र नाथ बसु एडवोकेट, बोनगांव दिनांक 6.6.68 पीएस गायघाटा, मौजा- नारिकेला बंदोबस्त प्लॉट नंबर 189 ऑफ .46 डिसमिल।

बंदोबस्ती प्लॉट संख्या 566 .84 डिसमिल में से .42 डिसमिल। बंदोबस्ती प्लॉट संख्या 416 का .14 डिसमिल बंदोबस्ती 413 का. 15 दशमलव.

कुल 1.17 एकड़ जमीन. एसडी/-

vi) आश्वासन के बावजूद, जब प्रतिवादी विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहे, तो वादी ने 7.5.1970 को मुंसिफ, बोनगांव के समक्ष मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि वादी को मुकदमे की जमीन पर कब्जा करने और कब्जा करने का पूरा अधिकार है। हालाँकि मुकदमा

खारिज कर दिया गया था, लेकिन अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 16.12.1985 के निर्णय द्वारा अपील को खारिज करते हुए आदेश में उल्लेख किया कि वादीगण ने विशिष्ट अनुपालना के लिए पारित निर्णय में निर्धारित तिथि से पहले विद्वान मुंसिफ के निर्देशानुसार धन जमा कर दिया है। प्रदर्शन।

34. तथ्यों और घटनाओं के उपरोक्त अनुक्रम से, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वादी-अपीलकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करने और समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थे। हमारी सुविचारित राय में, यहां ऊपर उल्लिखित निर्विवाद तथ्य और घटनाएं विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 16 (सी) की आवश्यकताओं के पर्याप्त अनुपालन के समान होंगी।

35. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों और यहां ऊपर चर्चा किए गए कानून को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

36. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और मुंसिफ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि करने वाले प्रथम अपीलीय

न्यायालय के निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील अलॉउड

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती परीक्षिता देथा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।